

फार्मा एसएमई की उत्पादन लागत 20% तक होगी कम

बिजनेस भास्कर ▶ नई दिल्ली...

फार्मा सेक्टर के छोटे और मझोले उपक्रमों (एसएमई) की गुणवत्ता, उत्पादकता और इन्वोएटिव क्षमता को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर फार्मा सेक्टर स्कीम शुरू की है। स्कीम के तहत कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित करने के लिए 20 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता सरकार देगी। इस स्कीम की मदद से एसएमई यूनिट को अपनी उत्पादन लागत 20 फीसदी तक कम करने में मदद मिलेगी। क्लस्टर स्कीम सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में लागू की जाएगी।

डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल विभाग की ओर से जारी किए गए नोट के मुताबिक स्कीम के लिए जरूरी मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए 12वीं योजना की शेष अवधि के लिए 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्कीम अगली पंचवर्षीय योजना में भी जारी रहेगी। कॉमन फैसिलिटी सेंटर के तहत कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटीज, ट्रेनिंग सेंटर, आरएंडडी सेंटर, ट्रीटमेंट प्लांट और कॉमन लॉजिस्टिक सेंटर स्थापित किया जा सकता है। इन गतिविधियों के अलावा क्लस्टर की जरूरतों के आधार पर स्टीयरिंग कमेटी दूसरी गतिविधियों के लिए भी प्रोजेक्ट को मंजूरी दे सकती है। एसएमई फार्मा यूनिट को इन सेंटरों की सेवाएं लेने के लिए एक

निश्चित यूजर्स चार्ज देना होगा। यह चार्ज छोटी यूनिट के लिए कम और मझोली यूनिट के लिए ज्यादा होगा। नोट में कहा गया है कि एसएमई फार्मा यूनिट को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने और फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री मजबूत बनाने के लिए इन्वोवेशन को बढ़ावा देने की जरूरत है। इसके लिए विश्व स्तरीय मैन्यूफैक्चरिंग फैसिलिटीज और इन्वोएटिव क्षमता के साथ-साथ बड़े पैमाने पर पूंजी का निवेश की दरकार होगी। फार्मा यूनिट खास कर एसएमई वित्तीय बाधाओं की वजह से खुद से ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं, वहीं विश्व स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञता की उपलब्धता एक और बड़ी बाधा है।

मदद

125

करोड़

रुपये मिलेंगे 12वीं योजना की शेष अवधि के लिए स्कीम को

20

करोड़ रुपये तक की वित्तीय मिलेगी कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित करने के लिए

एसएमई फार्मा यूनिट को मजबूत बनाने के लिए इन्वोवेशन को दिया जाएगा बढ़ावा